सेक्टर सात और दस बाजार में राजनीतिक फिरौतीबाजों का साया

विवेक की विशेष रपट

रिहायशी इलाके से बाजार में बदल चुके सेक्टर 7 और 10 में कातियाओं का भय? राजकुमार संतोषी की 1996 में आई सुपरहिट फिल्म घातक के यादगार गुंडे कातिया की मौत से सारा बाजार सुख का अनुभव करता है। शायद इसीलिए फिल्म की शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि इसके सभी पात्र और घटनाएँ काल्पनिक हैं। 7-10 मार्केट में सब वास्तविक है। तरबूज बेचने वाले विनोद पिछले 40 वर्षों से सेक्टर 10 और 7 के बीच से गुजरने वाली सड़क पर दुकान लगा रहे हैं। विनोद पहले खाली सड़क पर ठेली लगाते थे अब पूरी दुकान इसलिए क्योंकि फलों का भण्डार एक बड़ी दुकान जितना है पर लगाते अब भी सड़क पर ही हैं। कमेटी वाले आते हैं तो पहले से प्राप्त सूचना के तहत हटा लेते हैं और उनके जाते ही फिर लगा लेते हैं। इससे कमेटी वालों की इज्जत भी राह जाती है और उनका काम भी चलता रहता है।

अधेड़ उम्र के मुकेश 4 वर्षों से आम बेचते हैं और मौसमी फल भी। मुकेश की मानें तो वे संकरी सड़क के किनारे 8/10 के तिरपाल की दुकान बिना किसी की जेब गरम किये चला रहे हैं बड़ी खुशी से। सब्जियां बेच रहे गोलू जिसकी आयु बामुश्किल 17 वर्ष होगी, के अनुसार भी किसी को कोई रुपया नहीं दिया जाता न ही किसी तरह कि परेशानी पेश आती है। म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कभी हटाया नहीं, न ही तोड़-फोड़ जैसी कोई कार्यवाही ही की।

इन छोटे दुकानदारों कि बातें सुन कर ऐसा लगा जैसे रामराज्य कहीं है तो यहीं है। सोचा थोड़ी और पड़ताल की जाए और इसी क्रम में कई और छोटे-मोटे रेहड़ी पटरी वालों से बात करने की कोशिश की। सभी एक सुर में बोलते रहे कि यहाँ सब अच्छा है, किसी तरह की समस्या नहीं। जितना चाहो सड़क को घेर लो, दुकान को बढ़ा लो, सडक पर सामन रख कर बेचो, कोई कहने या पूछने वाला नहीं। आराम से कमाओ-खाओ। ये बात और थी कि उनके बताने के लहजे में डर का भाव उनके चेहरों पर सुगबुगाता हुआ उनके दिलों में होने का प्रमाण दे रहा था।

25 वर्षीय रामनरेश 5 साल पहले गोरखपुर से पलायन करके फरीदाबाद में रिक्शा चला रहे हैं। उनके लिए ये सबसे अच्छा बाजार है क्योंकि हमेशा खुले रहने वाले इस बाजार में सवारी मिलती रहती है और स्थानीय निवासी इतनी संकरी सड़क पर गाड़ी से आने की जगह रिक्शा से आना ज्यादा सुलभ मानते हैं। ये सब भाजपा का एक और सफल रोजगार मॉडल हो सकता है। छोटे दुकानदारों के असमंजस और साफ बात न करने के कारण कुकुरमुत्ते कि तरह इस स्वयं उपजे बाजार की हकीकत सामने नहीं आ रही थी। हम मार्किट एसोसिएशन के मुखिया मिस्टर अरोड़ा से मिलने उनके भव्य से जनरल स्टोर पर पहुँचे जहाँ जान पड़ा कि प्रधान जी तो ज्यादातर पास वाले एस डी रियल एस्टेट के दफ्तर पर ही मिलते हैं।

प्रधान जी से तो मुलाकात नहीं हो सकी पर एस डी रियल स्टेट के ऑफिस के एक वरिष्ठ सदस्य से बातचीत पर मालूम पड़ा कि ये सेक्टर फरीदाबाद के लोकप्रिय सेक्टर हैं। जितने पैसे में जमीन किसी और सेक्टर में 500 गज मिल सकती है, उतने में यहाँ एक तिहाई से भी कम जमीन मिलेगी। लोग क्या बेवकूफ हैं जो ऐसी जमीन इतने ज्यादा भाव से खरीदेंगे? रही बात अतिक्रमण की तो वो तो जनता की गलती है। शासन और प्रशासन की नहीं। भाजपा सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है इन छोटे मोटे मुद्दों को नजर अंदाज किया जाना चाहिए। ऑफिस से बाहर आने पर ऊपर लगे भाजपा के झंडे ने इन सज्जन का स्रोत बता दिया और दिल में बयाल आया- साफ दामन का दौर कबका खत्म हुआ / अब तो लोग अपने धब्बों पर गुरूर करते हैं।

हम सेक्टर 10 के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को ढूंढने के लिए सेक्टर के अन्दर तक गए। अतिक्रमण की पराकाष्ठा का सटीक रूप यहाँ देखने को मिला। पुरानी सीवर लाइन धीरे धीरे घरों और दुकानों की चौहद्दियों में घुस गई है और नयी लाइन के लिए सारी सड़क यहाँ-वहां खुदी पड़ी है। ज्यादातर सेक्टर में मुख्य सड़क के पास वाले लगभग सभी मकानों में दुकान खुली पड़ी हैं और कुछ तो आलीशान शोरूम का रूप भी ले चुके हैं।

अब तक मिले दुकानदारों ने सारगोई से कुछ नहीं कहा था पर अंतत: एक दुकानदार ने नाम न बताने की शर्त पर 'राम राज्य' की एक-एक गिरहें खोलनी शुरू कीं। उन्होंने बताया कि सब सरकारी जगह है पर वसूली के नाम पर कई प्रभावशाली लोग अपना अपना हिस्सा वसूलते हैं। ये बातें डर के मारे पूरे बाजार में कोई भी नहीं बताता क्योकि नाम पता चलते ही या तो दुकान बंद करा दी जाएगी या मार पीट भी हो सकती है।

कुछ दूर और चलने से एक सज्जन जिनकी अपनी खुद की भी एक अवैध दुकान थी, से मुलाकात हुई। उनका आक्रोश पहले तो सभी राजनैतिक पार्टियों पर अपशब्दों के साथ निकला, फिर घूमता हुआ सेक्टर 10 से ही नए जन्मे भाजपा के विधायक मूलचंद और मंत्री विपुल गोयल पर बरसा। उन्होंने भी अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हर रेहड़ी - खोमचे वाले से पैसे लिए जाते हैं। जिस दुकानदार की दुकान के आगे रेहड़ी या पटरी पर सामन बेचा जा रहा है वो भी पैसे लेता है।

दरअसल, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले भाजपाई अंदरखाने कांग्रेस के ही चेले बने पड़े हैं और कांग्रेस के ही ठोंडे विकास चौधरी के साथ मिल कर वसूली के धंधे की एक अलग अर्थव्यवस्था चला रखी है। ऐसी ही अर्थव्यवस्थाओं का खात्मा प्रधानमन्त्री मोदी ने नोटबंदी कर के समाप्त करने का दावा ठोंका था। औरों से अलग डर से कोसों दूर इन सज्जन ने आगे बताया कि इस अवैध बाजार में बैठने के लिए फूल वाले को बीस हजार रुपये, जूस वाले को साठ हजार, और तिरपाल के नीचे कोई भी दुकान लगाने वाले को कम से कम दस हजार रुपए इन गुंडारूपी नेताओं को देने पड़ते हैं।

सेक्टर 10 की हाउसिंग बोर्ड मार्किट के नाम पर सिर्फ चंद दुकानें मिलीं जिनका साइज 5/5 ही होगा और ऊँचाई भी बमुश्किल 5 फीट ही जान पड़ी। इन दुकानों को सुअरों का बाड़ा कहना ज्यादा तर्कसंगत है। विडम्बना देखिये कि इसी सड़क पर बने पीपलेश्वर मंदिर के लिए लम्बा चौड़ा मैदान और दीवारें मौजूद हैं। पास खड़ी एक महिला ने बताया कि इन दुकानों को लक्खा सिंह नामक व्यक्ति ने 27 लाख रुपये की बोली लगा कर ठेके पर लिया था। क्योंकि इसके मूल ढांचे में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता इसलिए उन्होंने दुकानें हाउसिंग बोर्ड को वापस कर दीं। तबसे ये कूड़ा घर के काम आती हैं और वहां चारों ओर फैली बजबजाती गन्दगी इस बात की पुष्टि कर रही थी।

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की कुरूपता ऐसी? शासन-प्रशासन सब मिल कर लूटने में लगे हैं। वहीँ जनता रोटी रोटी के बंदोबस्त में डरने को मजबूर है। संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता होगा पर इस बाजार के दुकानदारों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का गला घोंटा हुआ ही मिला। मोदी का 'ईज ऑफ डूइंग' सिर्फ और सिर्फ एफ डी आई तक सीमित है। भारत के छोटे कारोबारियों के लिए बस नोटबंदी जैसे राजनीतिक मिस एडवेंचर ही हैं। इन बाजारों के लूट पक्ष को बनाये रखने में ही 'सबका साथ सबका विकास' का नारा फलीभूत दिखता है।

स्मार्ट के नाम पर खजूर के पेड़ लगाकर ही फरीदाबाद जैसे शहरों को दुबई और शंघाई बनाने की मृगमारीचिका ऐसी है मानो नेपाह वायरस फैलाने वाले चमगाद? अब इंसानी शक्ल में व्यवस्था को संक्रमित कर रहे हैं। जिस व्यवस्था को सुचारु रूप प्रदान करना सरकारों का काम होना चाहिए था वहां सत्ता राजनीति के परजीवी अराजकता को जनता के लिए सुगम बना रहे हैं और सरकार की आँखे सिर्फ पत्थलगड़ी के सतायों में ही देश का खतरा ढूढ़ रही है।

बिल्डरों की मानें तो देश में जमीन के दाम औंधे मुह पड़े हैं। पर वहीँ इस सेक्टर में तीन गुने दाम क्यों है? इसलिए भी कि दाम चुकाओ एक हिस्से का और गुंडों को चढ़ावा चढ़ा कर कब्जा करो तीन गुने पर। ऐसे अराजक तत्वों से सरकारों की कानून व्यवस्था को भय क्यों नहीं? क्या भारत की संप्रभुता तब खंडित नहीं होती जब ऐसी ब्लैक इकॉनमी देश के भीतर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही चल रही हो? जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाते अधिकारी को ये सत्ता संरक्षित गुंडे गोली मार देते हैं? जल्द ही यदि शोध कर के इनको समाप्त न किया गया तो सिर्फ अहतियात से बचाव संभव नहीं होगा और संविधान में दर्ज स्वतंत्रताओं को एक एक करने मरने से रोक पाना शायद नामुमकिन ही होगा।

आसान है मोदी भक्त होना....

पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 13 दिनों से रोज बढ़ रहे हैं। पिछली सरकारों के समय दाम बढ़ते ही मोदी गिरोह सड़कों पर उतर आते थे और अब घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे, प्रतिक्रिया तो बहुत दूर की बात है। यह ठेका भाजपा आई टी सेल वालों ने उठा रखा है और वहीं मोदी भक्तों ने भी मोर्चा डट के संभाला हुआ है। उनके मुताबिक दाम क्यों बढ़ रहे हैं? बाजार में 50 वर्षीय अनिल राय ने बताया कि आरक्षण पर पलने वालों को पालने के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। पर ये पूछने पर कि क्या फिर दूसरी सरकारों का भी यही कारण होगा तो बोले नहीं, वो भ्रष्टाचार के कारण था। ये हुयी न एक सच्चे भक्त की निर्मल आत्मा!

जीवन के 45 बसंत देख चुके रोशन लाल किराना स्टोर चलाते हैं। अनिल राय को भी मात देते हुए रोशन जी बोले कि ये जो अरुण जेटली है ना वो अन्दर से कांग्रेस का है और और सारे पेट्रोल पंप इसी के हैं। बस यही कारण है कि ये दाम बढ़ा रहा है। मोदी जी ने दाम पर लगाम लगाई हुई है वरना आज ही 120 रूपये तक दाम चला जाएगा। रोशन जी से पूछा गया कि आप जो बिस्कुट बेचते हैं उसके दाम कौन तय करता है? तो उसी हिसाब से पेट्रोलियम के दाम कौन तय करता होगा? जवाब आया कि आप थोड़ा और गहरा ज्ञान प्राप्त करो अभी नादान हो, अर्थशास्त्र समझना सबके बस का नहीं है। ऐसी अंध मोदी भक्ति देख कर हम हरियाणा वासियों के बेहतर भविष्य की कामना ही कर सकते हैं।

तूतीकोरिन का नरसंहार, चुप है मीडिया और सरकार

थूथूकोडि उर्फ़ तूतीकोरिन में 'स्टरलाईट' द्वारा अपने प्रदूषित कारखाने के नाजायज विस्तार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी करके तमिलनाडु पुलिस ने 13 लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया।

अभी तक किसी भी सिविल अधिकारी ने पुलिस को गोली चलाने के आदेश देने की जिम्मेदारी नहीं ली है। हो सकता है 'स्टरलाईट' कंपनी से मोटा पैसा खाकर इन पुलिस वालों ने ये बहादुरी का कार्य खुद ही कर दिया हो। अभी तक किसी भी टीवी चैनल ने विस्तार से इस बारे में कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई है। केन्द्र सरकार की तरफ़ से तो इस पर लगभग मौनव्रत धारण किया हुआ है। उधर राज्य सरकार ने सरकारी खजाने यानी हमारे आप के पैसे से, पीड़ितों को मुआवज़ा देने की तो घोषणा कर दी है। लेकिन ये जुर्माना स्टरलाईट कंपनी से वसूला जायेगा ये कहते उनकी कंपकंपी छूट रही है। कुछ लोग, जाहिर है वो सरकार परस्त ही हैं, प्रदर्शनकारियों को उग्रवादी और आतंकवादी जाने क्या कह रहे हैं और पुलिस के इस हत्याकांड को जायज ठहरा रहे हैं। इसलिये जरा मामले की तह तक जाने की जरूरत है। खनिज ताम्बे से साफ़ करके शुद्ध तांबा बनाने की इस कारखाने की योजना 1995 में बनी थी। लेकिन क्योंकि इस से वातावरण को इतना ज्यादा नुक्सान होने की सम्भावना थी कि तीन राज्यों-गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात ने तो इसे अपने यहां लगाने की अनुमति देने से मना कर दिया। फ़िर झूठ बोलकर और जाहिर है कि मोटी रिश्वत देकर भी, कारखाने को तमिलनाडु में लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली गई। इन मामलों पर नज़र रखने वाली एक संस्था की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता नारायण का तो यहां तक कहना है कि इस मामले में जरूरी वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की रिपोर्ट भी झूठी तैयार की गई। ध्यान रहे कि इस तरह के प्रभाव की रिपोर्ट के लिये आस-पास के गांवों की कारखाना लगाने में सहमति जरूरी थी, जो नहीं ली गई। यह भी याद दिलाना उचित होगा कि इसी समूह की कंपनी को लोगों ने, लम्बे संघर्ष के बाद, मलकानगिरी में बाक्साईट का कारखाना लगाने से रोक दिया था।

यह भी बताया गया कि 2010 में भी मद्रास हाईकोर्ट ने वातावरण को नुक्सान पहुंचाने के कारण इस कारखाने को बंद कर दिया था। 2013 में इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 100 करोड़ जुर्माना लगा दिया था। लेकिन जुर्माना भरा गया या नहीं, पता नहीं। वैसे इस देश में ऐसे हत्यारों द्वारा जुर्माना भरे जाने के कम ही उदाहरण है।

मार्च 2013 में इस कारखाने से निकली गैस से बहुत सारे लोग बीमार हो गये थे। तब मजबूर होकर 29 मार्च को तमिलनाडु पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस कारखाने को बंद कर दिया था। लेकिन दिल्ली बैठे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इसे फ़िर चालू करवा दिया और कमीनापन यह कि प्रदूषण वाले मामले पर कुछ न कह कर पाल्यूशन बोर्ड के आदेश में कमी निकालकर, कारखाना खुलवा दिया गया। जाहिर है यह काम कोई मुफ़्त में तो हुआ नहीं होगा। दिल्ली के प्रदूषण पर रोज नागरिकों के प्रदूषण रहित, स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार का राग अलापने वाले किसी भी न्यायालय को तूतीकोरिन के नागरिकों के इस अधिकार की याद नहीं आई।

इस कारखाने से ताम्बा बनाने की प्रक्रिया में सलफ्यूरिक एसिड और फासफोटिक एसिड की भाप निकलती है जिससे लोगों की सेहत को नुक्सान होता है। सी.एस.ई. संस्था की सुनीता नारायण ने कहा, ''इस कारखाने के बेशर्मी से नियमों का उल्लंघन कर पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने के कारण, अपने जीवन के अधिकार के लिये लोगों का प्रदर्शण करना वाजिब था।'' शर्म की बात ये है कि रोज विदेशों में जाकर जबरदस्ती वहां के नेताओं से लिपटने और अपनी वाहवाही में तालियां बजवाने वाले प्रधानमंत्री को अपने ही देश के लोगों की हत्या पर कोई दुख नहीं है। ना कोई आंसू, न शोक संदेश, न मन की बात। न वाराणसी में पुल गिरने से मरने वालों के लिये न तूतीकोरिन में।

इसी बीच पुलिस फ़ायरिंग के कुछ फ़ोटो आये हैं, जिनमें कुछ लोगों को बस, वैन आदि की छतों पर चढ़कर और खड़े होकर भी फ़ायरिंग करते देखा जा सकता है। इनमें से कुछ सिविल ड्रेस में है। क्या ये पुलिस के लोग थे या स्टरलाइट। वेदान्ता के गुण्डे पुलिस के साथ मिलकर लोगों की हत्या कर रहे थे। पता चला है कि आन्दोलन के 13 में से छ: नेताओं को विशेषरूप से निशाना साधकर इन लोगों द्वारा मार डाला गया। ऐसी भी अपुष्ट सूचनायें हैं कि इन लोगों के पास स्नाइपर राफलें थी यानी ऐसी राइफलें जिन पर दूरबीन लगी हो। जाहिर है ऐसी राइफलें लेकर बसों पर चढ़कर गोली चलाने का सीधा-सीधा मतलब है कि सटीक निशाना लगाकर चुने हुये लोगों को मारना यानी नेताओं को मारना। तभी ये लोग आन्दोलन के 6 नेताओं को मार पाये। झूठ फैलाने वालों के लिये यह सूचना है कि यह आन्दोलन पिछले तीन महीने से चल रहा था और शान्तिपूर्ण था। ऐसा लगता है कि कुछ शरारती तत्वों को घुसाकर आंदोलन पर गोली चलाने का बहाना तैयार किया गया।

लेकिन अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने और चलवाने वाले नहीं जानते कि भूखी और दुखी जनता ना गोलियों से रुका करती है ना नेताओं के अभाव से।

-अजातशत्रु

सरकार का जनता पर बेशर्म हमला

पुलिस ने तामिलनाडू में पन्द्रह नागरिकों की गोली मार कर हत्या कर दी। ये नागरिक स्टरलाईट कम्पनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का विरोध कर रहे थे।

जिस कम्पनी के लिए सरकार अपने नागरिकों की हत्या कर सकती है उस कम्पनी के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि आप जब इस कम्पनी के बारे में जानेंगे तो आपको देश के विकास के नाम पर किये जाने वाले लूट और गुंडागर्दी के बारे में सच जानने को मिलेगा। स्टरलाईट कम्पनी का मालिक अनिल अग्रवाल है, इसकी मूल कम्पनी वेदांता है। अनिल अग्रवाल ब्रिटिश नागरिक है।

अनिल अग्रवाल कलकत्ता में रेलवे का चोरी का लोहा खरीदता था। चोरी का पैसा इकट्ठा होने के बाद वह रिश्वत और जालसाज़ी के दम पर आगे बढ़ता गया। इसकी ताकत इस बात से पता चलती है कि कांग्रेसी वित्त मंत्री चिदम्बरम इस का वकील था।

खुद को सुरक्षित रखने के लिए अनिल अग्रवाल इंग्लैण्ड भाग गया और बाद में इसने वेदांता कम्पनी बनाई। कांग्रेस के समय में इस कम्पनी को राजस्थान के ताम्बे की खदानें और कम्पनियां सौंप दी गई। छत्तीसगढ़ में इस कम्पनी को एल्युमिनियुम कम्पनी कौड़ियों के मोल बेच दी गई। जिस सरकारी कम्पनी के बैंक में पांच सौ करोड़ रुपया जमा था उस कम्पनी को वेदांता को पांच सौ करोड़ में बेचा गया।

एक बार इस कम्पनी की बड़ी चिमनी गिर गई जिसके नीचे सैंकड़ों मजदूर दब गये। छत्तीसगढ़ का भाजपा के गृह मंत्री बृज मोहन अग्रवाल ने आकर खुद हाजरी रजिस्टर फाड़ डाला था ताकि पता ना चल सके कि उस दिन काम पर कौन कौन से मजदूर हाजिर थे और मुआवजा ना देना पड़े। इसके बाद मजदूरों को निकाले बगैर बुलडोज़र लगा कर वहीं दबा दिया गया था।

इस वेदान्ता कम्पनी के लिए उड़ीसा के नियमगिरि पहाड़ पर रहने वाले आदिवासियों को पुलिस ने बहुत सताया। आखिर में कोर्ट ने बीच में आकर अनिल अग्रवाल की इस वेदांता कम्पनी को वहाँ से भगाया था।

एक बार इस बदनाम कम्पनी ने अपने लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाला गोल्डन पीकाक अवार्ड हथिया लिया था। यह अवार्ड पालमपुर हिमाचल में दिया जाना था लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह कार्यक्रम भंग कर दिया था। यह कम्पनी लूट रिश्वत बेईमानी पर्यावरण को नष्ट करने के लिए बदनाम है।

सरकारें इस कम्पनी को बचाने के लिए अपने नागरिकों पर वैसे ही गोलियां नहीं चलातीं। बदले में नेता और पुलिस अधिकारी इस कम्पनी से बड़ी रिश्वतें लेते हैं। आप जिस विकास के झांसे में आकर इन पूंजीपतियों का समर्थन देते हैं और अपने नेताओं की बातों में आकर मूर्ख बनते हैं, वह भ्रष्टाचार लूट और शुद्ध गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी में पुलिस, लुटेरे पूंजीपति के स्वार्थों की हिफाज़त करने के लिए सबसे आगे रहकर जनता पर हमला करती है।

- हिमांशु कुमार

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06